



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 मार्च, 1995/4 चैत्र, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 15th March, 1995

No. FDS B (1) 1/94.—The Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all earlier notifications issued in this behalf, in exercise of the powers vested in him under Section 9 & 10 of the Consumer Protection Act, 1986, hereby establishes a Consumer Disputes Redressal Forum to be known as the District Forum Dharamshala for the Revenue Districts of Kangra, Una and Chamba with its Headquarters at Dharamshala with immediate effect.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the District Forum Dharamshala shall consist of:—

- (a) a President who is, or who has been, or is qualified to be a District Judge; and
- (b) two other members to be appointed on part-time basis who shall be persons of ability, integrity and standing and have adequate knowledge or experience of, or

have shown capacity in dealing with, problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration, one of whom shall be a woman.

The Governor of Himachal Pradesh, is further pleased to direct that the District Forums functioning at present in the Districts Kangra, Una and Chamba shall cease to function *w.e.f.* the date of issue of this notification.

Shimla-2, the 15th March, 1995

No. FDS. II (1)1/94. The Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all earlier Notifications issued in this behalf, in exercise of the powers vested in him under Section 9 & 10 of the Consumer Protection Act, 1986, hereby establishes a Consumer Disputes Redressal Forum to be known as the District Forum, Mandi for the Revenue District of Mandi, Bilaspur, Hamirpur, Kullu and Lahaul & Spiti with its Headquarters at Mandi with immediate effect.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the District Forum, Mandi shall consist of :—

- (a) a President who is, or who has been or is qualified to be a District Judge; and
- (b) two other members to be appointed on part-time basis who shall be persons of ability, integrity and standing, and have adequate knowledge or experience of, or have shown capacity in dealing with, problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration, one of whom shall be a woman.

The Governor of Himachal Pradesh, is further pleased to direct that the District Forums functioning at present in the Districts Mandi, Bilaspur, Hamirpur, Kullu and Lahaul & Spiti shall cease to function *w. e. f.* the date of issue of this notification.

Shimla-171002, 15th March, 1995

No. FDS. II (1)1/94. The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986, is pleased to appoint Shri S. R. Singh, District & Sessions Judge as President, of the Consumer Disputes Redressal Forum to be known as the District Forum Mandi established *vide* Notification No. FDS. II (1)1/94, dated the 15th March, 1995 with effect from the date of assumption of the charge as such. The terms of appointment will be issued separately.

Shimla-2, the 15th March, 1995

No. FDS. II (1)1/94. The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986, is pleased to appoint Shri Rameshwar Sharma, District and Sessions Judge as President of the Consumer Disputes Redressal Forum to be known as the District Forum, Shimla established *vide* Notification No. FDS. II (1)1/94, dated the 15th March, 1995, with effect from the date of assumption of the charge as such. The terms of appointment will be issued separately.

Shimla-2, the 15th March, 1995

No. FDS. B(1)/94 - The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986, is pleased to appoint Shri C. P. Sharma, District and Sessions Judge as President of the Consumer Disputes Redressal Forum to be known the District Forum Kangra at Dharamshala established vide Notification No. FDS. B(1)/94, dated the 15th March, 1995 with effect from the date of assumption of the charge as such. The terms of appointment will be issued separately.

By order,

P. S. NEGI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

वन खेती एवं संरक्षण विभाग

शिमला

शिमला-171002, 10 मार्च, 1995

संख्या वन(ए) 4-3/91-भाग-2. - हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कुटलेहड़ वन सभादा (संवन्ध का अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन अधिनियम, धर्मशाला सर्कल, धर्मशाला, जिला कांगड़ा को, न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान करने हेतु, लिखित रूप में पत्रिवाद करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तियक एवं सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. VAN (A) 4-3/91-Vol. II, dated 10th March, 1995 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FOREST FARMING AND CONSERVATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th March, 1995

No. VAN (A) 4-3/91-Vol. II - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Kulehar Forest (Acquisition of Management) Act, 1992 (Act No. 19 of 1992), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare the Conservator of Forests, Dharamshala Circle, Dharamshala, District Kangra as authorised officer for making a complaint in writing to the court for taking cognizance of offences under the aforesaid Act.

By order,

Sd/-
Financial Commissioner-cum-Secretary (Fts).

शिमला-2, 10 मार्च, 1995

संख्या वन (ए) 4-3/91-भाग-2.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कुटलैहड़ वन सम्पदा (प्रबन्ध का अर्जन) अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल आयुक्त, कांगड़ा मण्डल, धर्मशाला को, इस प्रश्न को निनिश्चित करने के लिए, जब वही भी यह उठता है, कि क्या कोई व्यक्ति नियत दिन से तुरन्त पूर्व कुटलैहड़ वन सम्पदा में या से सम्बन्धित प्रबन्ध में पूर्णकालिक कर्मचारी था और उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन सरकारी कर्मचारी बन गया है, नियुक्त करत हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तियुक्त एवं सचिव (वन) ।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th March, 1995

No. Home (A)A (3)-1/94.—In supersession of this department notification of even number, dated 26th October, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Committee for framing of New Police Act, Police Rules and Jail Manual, with following as members :—

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Shri R. K. Srivastava,
Additional Director General of
Police. | <i>Chairman</i> |
| 2. Shri I. N. S. Sandhu,
Inspector General of
Prisons. | <i>Member-Secretary.</i> |
| 3. Shri Ravi Dhingra,
Divisional Commissioner,
Shimla. | <i>Member</i> |
| 4. Shri Kali Charan,
(Retd.) Deputy Inspector
General of Police. | <i>Member</i> |

2. The aforesaid committee will complete the task within three months from the date of issue of this notification.

By order,

Sd/-
Chief Secretary.

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 4 मार्च, 1995

संख्या एल० एस० जी०-एफ० (4) 4/94.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी०सी०) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उनके व्यय पर कार पार्किंग का निर्माण करने हेतु गांव स्टेशन वार्ड बड़ा शिमला, तहसील व जिला शिमला में भूमि अजित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित है या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सह्य प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर, लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला (एम्० डी० एम्० अरबन, शिमला) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : शिमला

गांव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
स्टेशन वार्ड, बड़ा शिमला	467	119.1 वर्ग गज

शिमला-2, 6 मार्च, 1995

संख्या एल० एस० जी०-एफ० (4) 3/94.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी०सी०) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा उनके व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव संजोली, तहसील व जिला शिमला में नाला निर्मित करने हेतु भूमि अजित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकाधिक, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अप्रक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला (एस0 डी0 एम0 अरबन शिमला) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : शिमला

गांव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
1	2	3
संजौली	1226	47.53 वर्गमीटर
	1224	16.56 "
	1235	5.00 "
	1236	11.00 "
	1237	10.10 "
	1163	16.50 "
	1156	2.00 "
	1131	3.50 "
	1130	5.65 "
	1133; 1134, 1824	223.55 "
		5.25 "
	1825	225.36 "
	योग कित्ता 12	602.70 वर्गमीटर

आदेश द्वारा,

एस0 के0 सूद;
आयुक्त एवं सचिव।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, 15th March, 1995

No. PBW (B&R)(B)3(i)155/94.—In supersession of this Department notification of even No., dated 6th January, 1995 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to offer the

following terms and conditions to Shri R. L. Sharma, District & Session Judge (Retd.) as Commission of Enquiry:—

- (i) he shall be paid a monthly honorarium equivalent to last pay drawn as District and Sessions Judge minus pension alongwith other allowances as admissible under the rules;
- (ii) he shall be provided with rent free accomodation;
- (iii) he shall be paid TA/DA as is admissible to Grade-I officers of the Government of Himachal Pradesh;
- (iv) he shall be entitled to receive Medical Facilities as is admissible to Grade-I officers to the Government of Himachal Pradesh.
- (v) he shall be provided with a vehicle for performing day to day duties and also for undertaking tours in connection with the enquiry.

The expenditure involved would be debitable to head of account No. 5054—Capital outlay on Roads and Bridges(P)796—Tribal sub-plan, 80—General, 001— Direction and Administration, 01—Salaries.

This issues with the concurrence of the Finance Department obtained vide their Dy. No. 61-Fin-C-B(7)-1/94, dated 24-1-1995.

By order,

R. K. ANAND,
Chief Secretary.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th March, 1995

No. PBW (B&R)(B)3(1)5/94.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to change the name of Satobari Totarani road to Mitra Sen Marg in Dharamshala, District Kagra (H. P.).

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 4 मार्च, 1995

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 38/94.—यतः श्री बाबू राम, प्रधान ग्राम पंचायत नम्होल, विकास खण्ड सदर, बिलासपुर को उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से उप-सम्भागीय अधिकारी (ना०) सदर बिलासपुर से छानबीन करवाने पर श्री बाबू राम, प्रधान पंचायत निधि व सरकारी धन के दुरुपयोग/छलहरण व विकास में जन सहयोग योजना के तहत प्राप्त राशि से निजी उपयोग हेतु सिचाई टैंक के निर्माण करके राशि के दुरुपयोग/छलहरण में संलिप्त पाये जाने पर आतिरिक्त सचिव, ग्रामाण विकास एवं पंचायती राज

द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 तथा ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7-11-94 का कारण बताया नोटिस जारी किया गया था।

श्रीर यह कि उक्त श्री बाबू राम, प्रधान ने उक्त कारण बताया नोटिस का उत्तर उपायुक्त, बिलासपुर को भेज दिया था, जो उपायुक्त बिलासपुर ने उप-मण्डल अधिकारी (ना०) सदर को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजा था।

श्रीर यह कि उप मण्डल अधिकारी (ना०) सदर ने अपनी टिप्पणियों में यह स्पष्ट किया है कि उनका उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि बिना मक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पंचायत निधि से विकास में जन राहयोग के अन्तर्गत धन का दिया जाता नियमों के प्रतिकूल है। ब सरकारी अनुदान की निजी टैंक का निर्माण कर अनुदान राशि का दुरुपयोग है।

श्रीर यह कि उक्त श्री बाबू राम, प्रधान से प्राप्त उत्तर तथा उप-मण्डल अधिकारी (ना०) बिलासपुर सदर द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार किया गया तथा उत्तर अस्तोपजनक पाया गया।

श्रीर यह कि उक्त मामले के सभी पहलुओं/तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करने पर यह पाया गया कि उक्त श्री बाबू राम का प्रधान पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं, श्रीर प्रधान पद से निलम्बन आवश्यक है ताकि वह पंचायत अभिलेख में किसी प्रकार का फेरबदल न कर सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत प्राप्त हैं का प्रयोग करने हुए श्री बाबू राम, प्रधान ग्राम पंचायत नम्हान, बिलासपुर सदर, जिना बिलासपुर को प्रधान पद से निलम्बन करने के महर्ष आदेश देते हैं, यह भी आदेश देते हैं कि उनके पास पंचायत का कोई अभिलेख, धन या अन्य सम्पति हो जो उसे ऐसे अभिलेख, धन या सम्पति को पंचायत के सचिव को सौंप दें, तथा उन्हें पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से बर्चित लिया जाता है।

शिमला-171002, 12 मार्च, 1995

संख्या पी० सी० एच०-एच० की० (3)/278.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 17 नवम्बर, 1993 का प्रसंग जारी रखते हुए, श्री प्रीतम सिंह, प्रधानाचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बेजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में तदर्थ पदोन्नति की अवधि को जून, 1994 से आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव